भारतीय अर्थव्यवस्था : स्थिरता के साथ वृद्धि की संभावनाएँ *

डॉ. . वाइ. वी. रेड्डी

मैं सिंगापुर के नीति-निर्धारकों, प्रसिद्ध विद्वानों और बाजार सहभागियों की इस भव्य सभा को संबोधित करने के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान के प्रति हृदय से आभारी हूँ। सिंगापुर विश्व का एक महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र और एशियाई क्षेत्र में आर्थिक सहयोग की दृष्टि से भारत का एक अत्यंत विशेष साझेदार है। मैं अपने मित्र श्री हेंग स्वी कीट के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने यह निमंत्रण स्वीकार करने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। हम अनेक अंतरराष्ट्रीय सभाओं के संबंध में अकसर मिलते हैं तथा आपस में टिप्पणियों, सरोकारों और सुविधाओं का आदान-प्रदान करते हैं। अगस्त 2007 में भारतीय रिज़र्व बैंक में उनका स्वागत करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने हमारे समक्ष सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (एएसईएएन) की कार्यपद्धति का एक बढ़िया विवरण प्रस्तुत किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक और एमएएस के बीच घनिष्ठ सहयोग की दिशा में पहले कदम के रूप में हमने मार्च 2008 में डीबीएस बैंक, सिंगापुर को आठ शाखाएँ खोलने के लिए अपना अनुमोदन सूचित कर दिया है। उसी दिन हमने युनाइटेड ओवरसीज़ बैंक लि. को मुंबई में उनकी प्रथम शाखा खोलने के लिए भी अपना अनुमोदन सूचित कर दिया है। लगभग संपूर्ण देशी बैंकों के समान बैंकिंग का समूचा कार्यक्षेत्र और इससे संबंधित गतिविधियाँ प्रारंभ करने के लिए उक्त शाखाओं को प्राप्त होनेवाली स्वतंत्रता की दृष्टि से एवं इस तथ्य को भी देखते हुए कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) से संबंधित हमारे दायित्वों के अनुसार हमारे लिए एक वर्ष में बारह विदेशी बैंक शाखाओं का अनुमोदन करना अपेक्षित है, ये अनुमोदन महत्वपूर्ण हैं। रिज़र्व बैंक के हम भारतीय बैंकों के लिए नई शाखा लाइसेंस देने में और विशेष रूप से 25 अप्रैल 2008 से प्रभावी रूप में क्यूएफबी की विशेष सुविधाओं

*डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान, सिंगापुर में 20 मई 2008 को दिया गया व्याख्यान ।

के साथ संपूर्ण बैंक लाइसेंस हेतु भारतीय स्टेट बैंक को अनुमोदन प्रदान करने के लिए एमएएस द्वारा दर्शाये गये सोच-विचार और अनुकूल दृष्टिकोण की अत्यंत सराहना करते हैं। मेरी इस यात्रा का उद्देश्य दोनों मौद्रिक प्राधिकारियों और दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक उत्पादक और परस्पर लाभकारी संबंध को सरकारी और निजी क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए और मजबूत बनाना है। मैंने इस संबंध में आज ही इसके पहले श्री हेंग स्वी कीट के साथ उनके कार्यालय में मुलाकात की है। मैं श्री थर्मन षण्मुगरत्नम, माननीय वित्त मंत्री से शीघ्र ही मिलनेवाला हूँ क्योंकि मैं, अन्य बातों के साथ-साथ, जी30 सभाओं (कान्क्लेव्ज़) सहित अनेक मंचों पर उनकी विद्वत्ता और वाक्पटुता का साक्षी रहा हूँ।

आज मैं अपने संक्षिप्त भाषण में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को रेखांकित करते हुए अल्पावधि और मध्यावधि दोनों में स्थिरता सहित वृद्धि के लिए भारत की संभावनाओं पर कुछ टिप्पणियाँ करूँगा। उसके बाद होनेवाली चर्चा में हम आज की सभा की दिलचस्पी के अनुरूप प्रमुख केंद्रबिंदु एवं विशिष्ट बिंदुओं पर भी विचार-विमर्श कर सकेंगे।

अल्पावधि की संभावनाएँ

नीतिगत प्रयोजनों के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि वर्ष 2008-2009 (मार्च 2009 के साथ समाप्त होनेवाले वर्ष) के लिए 8 से 8.5 प्रतिशत के दायरे में होने का अनुमान किया गया है। यह अनुमान यथार्थपरक है, यह मानने के लिए अनेक कारण हैं। पिछले पाँच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रति वर्ष 8.7 प्रतिशत के औसत से विस्तार हुआ है। वास्तव में, जीडीपी वृद्धि 2006-2007 में 9.6 प्रतिशत थी और यह 2007-2008 में अनुमानित 8.7 प्रतिशत पर कम हुई है। इस कमी के लिए, निवेशों के रूप में आपूर्ति की ओर प्रतिक्रियाओं में वृद्धि करने के लिए परिवेश को समर्थ बनाना जारी रखते हुए अत्यधिक माँग के दबावों को कम करने के लिए अपेक्षित पूर्वक्रियात्मक मौद्रिक नीति संबंधी कार्यवाइयां अंशतः कारण हैं। एक ओर जहाँ वैश्विक कारकों का बढ़ता हुआ महत्व है, वहीं दूसरी ओर भारत की वृद्धि मुख्य रूप से देशी माँग और पूर्ति के कारकों द्वारा संचालित है। सकल देशी बचत जीडीपी के लगभग 35 प्रतिशत पर जारी है तथा उपलब्ध साक्ष्य उत्पादकता में निरंतर वृद्धि का संकेत करता है। चालू वर्ष में अनुमानित वृद्धि की प्राप्ति सामान्य मानसून और वैश्विक वृद्धि में वर्तमान में अनुमानित से अनधिक मंदी के कारण संभव होगी।

भारत में मौद्रिक नीति निर्धन जनता के बड़े खंड, जो बचाव से रहित है, के लिए मूल्य स्थिरता के महत्व को पहचानते हुए मूल्य स्थिरता को उचित प्राथमिकता देती है। इसके अलावा, मौद्रिक नीति यह मानती है कि उच्च वृद्धि का लाभ गरीब जनता को विलंब से मिलता है जबकि मुद्रास्फीति का प्रतिकूल प्रभाव उन पर तत्काल पड़ता है। अतः मुद्रास्फीति का वर्तमान उच्च स्तर, विशेष रूप से मुद्रास्फीति के अनुमानों पर प्रभाव के रूप में पूर्णतः अस्वीकार्य है। तथापि, मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति के वर्तमान दौर की जटिलताओं को समझती है। तदनुसार, आवश्यकता के अनुसार अन्य सभी उपायों का सहारा लेने के विकल्प सहित हाल में चलनिधि के प्रबंध पर जोर दिया गया है ताकि बाजारों से पूर्ति संबंधी प्रतिक्रियाओं तथा केंद्र और राज्य सरकारों से प्रतिक्रियाओं के अनुरूप माँग संबंधी दबावों को नियंत्रित किया जा सके।

वार्षिक नीति के अंतर्गत 2008-2009 में 16.5 प्रतिशत से 17 प्रतिशत के दायरे में मुद्रा आपूर्ति की कम की गई दर के लिए योजना है जबकि तदनुरूप खाद्येतर ऋण की वृद्धि लगभग 20 प्रतिशत पर रखी

गई है। संकेतों के अनुसार, जैसे ही मौद्रिक, राजकोषीय और प्रशासनिक उपाय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे, थोक मूल्य सूचकांक के वर्तमान में बढ़े हुए स्तर का उल्लेखनीय रूप में कम होना प्रारंभ हो सकता है जबकि अन्य मौसमी और वैश्विक कारक अनुकूल हो जाएंगे। जैसा कि वार्षिक नीति में उल्लेख किया गया है, उक्त नीति का प्रयास वैश्विक रूप से प्रसारित मुद्रास्फीति में उत्पन्न हो रही जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र मुद्रास्फीति को 5.0 प्रतिशत के यथासंभव नजदीक लाने की अधिमानता के साथ हेडलाइन मुद्रास्फीति को 2008-09 में लगभग 5.5 प्रतिशत तक लाने का रहेगा। यह संकल्प इस उद्देश्य के साथ आगे जारी रहेगा कि मुद्रास्फीति संबंधी नीति और संकल्पनाओं को 4.0-4.5 प्रतिशत के दायरे में अनुकूलित किया जाए ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत के व्यापक स्तर पर समेकन और मध्यावधि में स्व-त्वरणशील वृद्धि को बनाए रखने के लक्ष्य के अनुरूप मुद्रास्फीति की लगभग 3.0 प्रतिशत की दर एक मध्यावधि लक्ष्य बन सके। रिज़र्व बैंक किसी भी समय देशी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई विपत्तियों के उत्पन्न होने की स्थिति में उनके प्रति तत्काल और उचित रूप में प्रतिक्रिया दिखाने के लिए तैयार है।

यह उल्लेखनीय है कि विदेशों में वित्तीय अस्तव्यस्तता से देशी वित्तीय बाजार गंभीर रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं, सिवाय इसके कि इक्विटी बाजार में उतार-चढ़ाव में कुछ वृद्धि हुई है जो अपेक्षाकृत अधिक खुला है। उपलब्ध संकेत सरकारी प्रतिभूति बाजार; निरंतर मजबूत और बनाए रखने लायक बाह्य क्षेत्र की दृष्टि से विदेशी मुद्रा बाजार; तथा चलनिधि के प्रबंध पर फोकस द्वारा विधिवत समर्थित मुद्रा बाजार में निरंतर स्थिरता निर्दिष्ट करते हैं। एक ओर जहाँ व्यापार खाते पर बढ़े हुए तेल मूल्यों द्वारा प्रभाव पड़ सकता है, वहीं दूसरी ओर चालू खाता घाटे का मामूली रूप में बने रहने का अनुमान है जो मजबूत अदृश्य मदों (इन्विज़िबल्स) की बदौलत है तथा प्रत्याशित निवल पूँजी अंतर्वाहों द्वारा इसकी पूर्ति सुविधापूर्वक हो सकती है।

वित्तीय संस्थाओं के संबंध में कार्यकुशलता और लचीलेपन में वृद्धि संबंधी सुधारों के जारी रहने के संकेत हैं। भारत में बैंकों की प्रधानता वाला वित्तीय क्षेत्र है तथा देश में प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक के पास नौ प्रतिशत के न्यूनतम निर्धारित अनुपात की तुलना में अधिक पूँजी पर्याप्तता है। वास्तव में, ओवरहीटिंग के प्रारंभिक संकेतों को संयत करने के लिए मौद्रिक उपायों को सहायता पहुँचाने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा समयबद्ध रूप में प्रावधानीकरण और जोखिम-भारित अपेक्षाओं के संबंध में कड़ाई बरती गई है। रिज़र्व बैंक जमाकर्ताओं के हित, आम आदमी की सेवा, वित्तीय समावेशन तथा कुशलता में बढ़ोतरी द्वारा वृद्धि के लिए समर्थक परिवेश पर बल देते हुए वित्तीय स्थिरता को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखता है।

संक्षेप में, स्थिरता के उचित आश्वासन के साथ प्रभावी वृद्धि के लिए अल्पावधि संभावनाएँ निरंतर उज्ज्वल बनी हुई हैं यद्यपि वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण ये कुछ मंद हो गई थीं। भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल तत्वों के लिए अतिरंजित मंदी के रुख की आवश्यकता नहीं है जो अब कहीं-कहीं देखा जा रहा है, वैसे ही जैसे पहले की अवधियों में अतिरंजित तेजी का रुख उचित नहीं था। मुद्रास्फीति के अनुमानों को नियंत्रित करने और वृद्धि की संभावनाओं को बनाये रखने की वर्तमान समस्याओं का समाधान करना उक्त नीति के अंतर्गत जारी रहेगा।

मध्यावधि की संभावनाएँ

प्रति व्यक्ति निम्न आय से युक्त एक बड़ी और विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था, जो एक अत्यंत अनिश्चित वैश्विक परिवेश में संरचनागत परिवर्तन से गुजर रही है, के लिए सार्वजनिक नीति हेतु चुनौतियाँ कई प्रकार की हैं। मैं कुछ चुनौतियों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूँ जिन्हें हम रिज़र्व बैंक में साम्यिक वृद्धि हेतु मध्यावधि संभावनाओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं।

पहले, जबकि 60 प्रतिशत से अधिक श्रमशक्ति कृषि पर आधारित है, इस क्षेत्र से जीडीपी के 20 प्रतिशत से भी कम योगदान है। इसके अलावा, जीडीपी की कृषि से होनेवाली वृद्धि जनसंख्या की वृद्धि की दर से केवल सीमांत रूप से अधिक है जो गरीबी में तेजी से कमी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कृषि उत्पादन में अस्थिरता के कारण न केवल समग्र वृद्धि के लिए, बल्कि जैसा कि हाल के अनुभव ने प्रचुर मात्रा में दर्शाया है, निम्न और स्थिर मुद्रास्फीति बनाए रखने के लिए भी चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। कृषि क्षेत्र की बढ़ाई गई वृद्धि खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, मूल्य स्थिरता, समग्र अंतर्विष्ट वृद्धि और समग्र अर्थव्यवस्था की संवृद्धि की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अत्यावश्यक है। हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11वीं योजना अवधि के दौरान कृषि की वृद्धि दर को 4.0 प्रतिशत तक दुगुनी करने के लिए एक प्रमुख योजना की घोषणा की। खाद्य उत्पादों की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने और तीन साल के अंदर उनकी उपलब्धता में दर्शनीय परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए भी एक समयबद्ध खाद्य सुरक्षा मिशन की घोषणा की गई।

दूसरे, आधुनिक बुनियादी संरचना की अपर्याप्त उपलब्धता और कुशल मानवशक्ति की कमी विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवरोध हैं। यह आवश्यक है कि इस उद्योग की उन्नति हेतु परिवेश को अनुकूल बनाने के लिए मौजूदा बुनियादी संरचना की सुविधाओं, खास तौर से सड़कों, पत्तनों और बिजली की सुविधाओं में वृद्धि की जाए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे तो विनियामक ढाँचा और समग्र निवेश का वातावरण हैं जिनका समाधान सरकार द्वारा किया जा रहा है। एक अन्य चिंता की बात लागत की वसूली रही है जिसके संबंध में यह प्रत्याशित है कि प्रबुद्ध सरकारी और निजी साझेदारी के चलते इसमें सुधार होगा। उभरती हुई माँग के दबावों का सामना करने के लिए भौतिक बुनियादी संरचना में कुशल और तत्पर सुधार लाने के लिए भारत के पास घरेलू तौर पर अभिकल्प, निर्माण, प्रौद्योगिकीय, संगठनात्मक और वित्तीय क्षमताएँ हैं।

तीसरे, चक्रीय तत्वों को हिसाब में लेने के बाद भी, हाल के वर्षों में राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया की एक मुख्य विशेषता प्रमुख घाटे के संकेतकों में महत्वपूर्ण कमी रही है। रिज़र्व बैंक में राज्य वित्तों से संबंधित हमारे अध्ययन से उनकी राजकोषीय स्थिति के संबंध में आशावाद के लिए आधार मिलता है। वास्तव में, कुछ राज्य सरकारें बाजार से अपना कर्ज वापस खरीद रही हैं तथा कुछ अन्य राज्य सरकारें अपने नियोजित बाजार उधार कम कर रही हैं। हमने दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है तथा यदि इनका समाधान किया जाए तो इसके परिणामस्वरूप दोनों केंद्र और राज्यों के स्तरों पर राजकोषीय सशक्तीकरण होगा। एक तो आर्थिक सहायता (सब्सिडी) में कमी करना, जो अनुचित और प्रत्यक्षतः निर्धनों के प्रति अलक्षित आर्थिक सहायता को समाप्त करके किया जा सकता है, तथा दूसरा अधिकांश विकृत कर-छूटों को समाप्त करना। हमारी जनता के एक बड़े भाग को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएँ मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती है।

चौथे, आवधिक सर्वेक्षणों पर आधारित बेरोजगारी की दर पिछले पंद्रह वर्षों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में बढ़ गई है और यह वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में तेज रही है जो कृषि में मंदी को प्रतिबिंबित करती है। एक सकारात्मक लक्षण यह रहा है कि गरीबी के अनुपात में उल्लेखनीय कमी आई है, लेकिन गरीबों की संख्या अभी भी अत्यधिक है। स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक नीति के लिए अत्यधिक प्राथमिकता के कारण रोजगार का निर्माण हो रहा है और गरीबी में कमी आ रही है। हाल में लागू की गई कुछ रोजगार गारंटी योजनाओं का उद्देश्य इनमें से कुछ समस्याओं का समाधान करना है तथा रिज़र्व बैंक बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के कार्यक्रम के माध्यम से एक सहायक भूमिका अदा कर रहा है।

अंत में, भारत में यह मान्यता बढ़ रही है कि राज्य की क्षमता को मजबूत करने में शासकीय सुधार महत्वपूर्ण हैं तथा इनसे वह अपने मुख्य कार्यों का निष्पादन कर सकता है। आर्थिक शासन संबंधी संस्थाओं में सुधार लाने के कार्य के अंतर्गत अन्यों के साथ-साथ बाजारों के कुशल कार्यचालन के लिए अत्यावश्यक अनेक संगठन और कार्य शामिल हैं। इस बात की पहचान की गई है कि अच्छे शासन का सह-अस्तित्व तभी संभव है जब सरकारी क्षेत्र न्यायोचित रूप से और कुशलतापूर्वक कार्य करता है जिसे उसमें सुधार लाकर ही प्राप्त किया जा सकता है, न कि उसे दुर्बल बनाकर। अतः सरकारी संस्थाओं में सुधार लाने और उन्हें सशक्त बनाने में व्यापारी समुदाय का महत्त्वपूर्ण हित है।

उपर्युक्त चुनौतियों को ध्यान में रखने के बाद भी मध्यावधि में वृद्धि की गति और स्थिरता के संबंध में आशावादिता के कारण हैं। सकल देशी बचत और कुल कारक उत्पादकता में निरंतर बढ़ोतरी संभाव्य उत्पादन के वृद्धिशील स्तर को निर्दिष्ट करती है। स्व-संपोषक और गतिवर्धक प्रतिस्पर्धी शक्तियाँ हैं जैसा कि भारतीय कंपनियों की विश्व स्तर पर मौजूदगी तथा भारत में वैश्विक कंपनियों की रुचि से स्पष्ट है। बचत और निवेश के संतुलन एवं बाह्य क्षेत्र से भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्यमान मजबूती और समुत्थान-शक्ति प्रतिबिंबित होती है। वास्तविक अर्थव्यवस्था में किए गए व्यष्टि-संरचनात्मक सुधारों से कुछ राज्यों में अच्छे परिणाम निकल रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उनके देशी उत्पाद में दो अंकों वाली वार्षिक वृद्धि परिलक्षित होती है। अन्य राज्य वृद्धि के इन पुरोगामियों द्वारा कायम किए गए उदाहरण का अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं।

कुछ ऐसी 'आसानी से परिमाण निर्धारित न की जा सकने वाली शक्तियाँ' हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के पास हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकों का विपुल समूह और अंग्रेजी भाषा से परिचित करोड़ों लोग शक्ति के स्रोत हैं। भारत में अनेक भाषाओं का ज्ञान लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वे बहुविध-संस्कृतियों की स्थितियों के प्रति अपने आपको बेहतर अनुकूल कर लें जिससे वे अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों में स्वयं को आसानी से योग्य बना सकें। केंद्र और कई राज्यों में मिलेजुले मंत्रिमंडलों एवं आवधिक चुनावों के होते हुए भी राजनैतिक माहौल की एक विशेषता है जिसे राजनैतिक व्यवस्था की स्थिरता कहा जा सकता है। आनेवाले कुछ दशकों में भारत विश्व में सबसे युवा देशों में से एक रहेगा। इस "जनसांख्यिकीय लाभांश" को एक अवश्यंभावी लाभ के रूप में देखा जाता है बशर्ते कि इसे प्राप्त करने के लिए कौशल-उन्नयन और समर्थ शासन जैसी पूर्वापेक्षाएं पूरी की जाती हों। व्यावसायिक वातावरण के तौर पर अर्थव्यवस्था की बाजार-उन्मुखता से युक्त प्रभावकारी वृद्धि एक विस्तृत आधार वाले और वृद्धिशील उद्यमी वर्ग के साथ एक 'बॉटम अप' प्रयोग रही है। ये प्रवृत्तियाँ संभवतः भारत में पहले से ही विद्यमान बड़े और वृद्धिशील उद्यमी वर्ग, जो व्यावसायिकता के साथ

ओतप्रोत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना चाहता है, के अंतर्गत नवीनता के प्रति अभिरुचि को प्रतिबिंबित करती हैं।

संक्षेप में, मध्यावधि चुनौतियाँ कई हैं, परंतु सभी संकेत, उचित स्थिरता के साथ, वृद्धि की पहले से ही विद्यमान उच्च दर में कुछ गतिवर्धन के लिए समग्र आशावादिता की भावना की ओर निर्देश करते हैं। शायद हमें अपने ध्यान में केवल भारत में अरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी को ही नहीं, बल्कि लाखों गरीब और बेरोजगार जनता की संख्या में कमी को भी रखना चाहिए। कुछ पर्यवेक्षकों की राय में भारत की आर्थिक प्रगति दुनिया में एक प्रमुख शक्तिकेंद्र (पावरहाउस) की शुरुआत को दर्शाती है। परंतु हममें से कई के लिए मध्यावधि के संबंध में आशावादिता भारत में करोड़ों लोगों के लिए आधारभूत पोषण, स्वच्छ पानी, अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षात्मक स्वस्थता, न्यूनतम आवास-व्यवस्था, वैयक्तिक सुरक्षा और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए एक दुर्गम यात्रा का प्रारंभ ही है। भारत में वृद्धि और स्थिरता के लिए संभावनाएँ महत्वपूर्ण हैं, परंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण तो सार्वजनिक नीति के मूल उद्देश्यों को पूरा करने में आनेवाली चुनौतियाँ हैं।

निष्कर्ष

मैं अपनी बात नई दिल्ली में 21 नवंबर 2005 को मंत्री परामर्शदाता ली कुआन यू द्वारा दिये गये जवाहरलाल नेहरू स्मृति व्याख्यान से कुछ उद्धरण देकर समाप्त करना चाहूँगा।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के अवसर पर प्रसारित नेहरू जी के व्याख्यान की अविस्मरणीय शुरुआत को याद करते हुए मंत्री परामर्शदाता ली कुआन यू ने कहा, "नेहरू ने जिस नियति की परिकल्पना की थी, वह एक आधुनिक, औद्योगीकृत, लोकतंत्रीय और धर्मनिरपेक्ष भारत की थी जो बीसवीं सदी के उत्तरार्ध के बृहत्तर ऐतिहासिक प्रवाह में अपना स्थान ग्रहण करेगा।"

"विश्व में भारत के स्थान और एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत के बारे में नेहरू का दृष्टिकोण भारत की पकड़ में है।"

"एक बिलियन भारतीयों का भविष्य दाँव पर है, खोये हुए बहुत समय की भरपाई के लिए भारत को जागना होगा।"

"नियति के साथ भारत के अगले मिलन का समय आ गया है।"